

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2463
जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

विभिन्न राज्यों में भूजल क्षरण की दर

2463. श्री आशीष दुबे:

श्री धर्मबीर सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल का स्तर लगातार कम होता जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग जैसे राज्यों में भूजल स्तर की कमी की दर का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण अथवा आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई और अकुशल सिंचाई पद्धतियों सहित भूजल स्तर में तेजी से गिरावट के क्याकारण हैं;
- (घ) सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;
- (ङ) क्या सरकार अत्यधिक भूजल दोहन करने वाले उद्योगों और व्यवसायों पर सख्त नियम लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जल-किफ़ायती सिंचाई पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किसी वित्तीय योजना या प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क):केन्द्रीयभूमिजलबोर्ड

(सीजीडब्ल्यूबी)

औरसंबंधितराज्यनोडल/भूजलविभागद्वारासंयुक्तरूपसेवार्षिक आधार पर देशकेडॉयनेमिक भूमिजलसंसाधनोंकाआकलनकियाजारहाहै। वर्ष 2017 केआकलनऔरवर्ष 2024 केआंकड़ोंकीतुलनाकरनेपरयहपाया गयाहैकिदेशमेंकुलवार्षिकभूजलपुनर्भरण 432 बिलियनक्यूबिकमीटर (बीसीएम) सेबढ़कर 446.9 बीसीएमहोगयाहैतथा इसी अवधिकेदौरानदेशमेंकुलनिष्कर्षणयोग्यभूजल 393 बिलियनक्यूबिकमीटर (बीसीएम) सेबढ़कर 406 बीसीएमहोगयाहै। इसकेअतिरिक्त, भूमिजलनिष्कर्षण (एसओई) काचरण,

जिसे कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूमि जल संसाधनों की तुलना में सभी प्रयोजनों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, इसी अवधि के दौरान 63% से घटकर 60.47% हो गया है, जो क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद देश में भूजल की समग्र स्थिति में सुधार का संकेत है।

(ख): पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जबलपुर प्रभाग में वर्ष 2017 और 2024 के लिए उपलब्ध कुल निष्कर्षण योग्य भूजल के तुलनात्मक आंकड़े **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मानसून पश्चात वर्ष 2024 के जल स्तर की तुलना पिछले पांच वर्षों के औसत से करते हुए उक्त राज्यों में भूजल स्तर के उतार-चढ़ाव का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): तीव्र गति से औद्योगिकीकरण की बढ़ती आवश्यकता, निरंतर शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, जल की अधीत खपत वाली फसलों के प्रतिकिसानों का रूझान, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि घटक देश के भूजल संसाधनों पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारक हैं।

(घ): जल राज्य का विषय है, भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करती है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में भूजल स्तर में सुधार और भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

- I. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन कर रही है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर एक समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए का कार्यान्वयन वर्ष 2024 से किया जा रहा है, जिसमें देश के जल संकट का सामना करने वाले 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
- II. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) भूजल का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की एक व्यापक रूपरेखा का प्रावधान किया गया है।

- III. सीजीडब्ल्यूबीद्वारा जलभृतविन्यास और इसके विशिष्टीकरण कीरूपरेखातैयारकरनेकेउद्देश्यसेराष्ट्रीयजलभृतमैपिंग औरप्रबंधनकार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) की शुरुआत की गई है। इसयोजनाकेतहतदेशकेलगभग 25 लाखवर्गकिलोमीटरकेसमस्त मैपिंग योग्यक्षेत्रकामैपिंग कियागयाहैऔरकृत्रिमपुनर्भरणकेलिएइसे सिफारिशोंसहितप्रबंधनयोजनाओंकोकार्यान्वयनकेलिएसंबंधितराज्यसरकारोंकेसाथसाझाकियागयाहै।
- IV. भारतसरकारद्वारामिशनअमृतसरोवरकी शुरुआत की गयी थी,जिसकाउद्देश्यदेशकेप्रत्येकजिलेमेंकमसेकम 75 जलनिकायोंकाविकासऔरपुनरुद्धार करनाथा। इसकेपरिणामस्वरूपदेशमेंलगभग 69,000 अमृतसरोवरकानिर्माण/पुनरुद्धार कियागयाहै।
- V. जलशक्तिअभियानकीगतिमें और अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से जलसंचयनभागीदारी,भारतमेंजलसंस्कार,जलकी स्थायित्वता केलिएसमुदाय-आधारित आंदोलन का माननीय प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीद्वारादिनांक 6 सितंबर, 2024 कोसूरत, गुजरातमेंदेशमेंवर्षाजलसंचयनकोएकजनआंदोलनबनानेकीदृष्टिसेशुभारंभ कियागयाहै। इस पहल के माध्यम से सामुदायिकस्वामित्वऔरजिम्मेदारीकोबढ़ावादेते हुए विभिन्नक्षेत्रोंमेंविशिष्टजलचुनौतियोंकेअनुरूपलागतप्रभावी, स्थानीयसमाधानविकसितकरने का प्रयास किया गया है।
- VI. आवासन औरशहरीकार्यमंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों केलिएमॉडलभवन उप नियम (एमबीबीएल), 2016 तैयारकिएहैं, जिसमेंवर्षाजलसंचयनऔरजलसंरक्षणउपायोंकीआवश्यकतापरपर्याप्तध्यानदियागयाहै। एम बीबीएलकेअनुसार 100 वर्गमीटरयाउससेअधिककेभूखंडकेआकारवालेसभीभवनोंमेंवर्षाजलसंचयनके समग्र प्रस्तावको अनिवार्यरूपसेशामिलकिया जाना होगा। 35 राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंद्वारा मॉडलउप-नियमोंकोअपनालियागया है।
- VII. जलशक्तिमंत्रालयद्वारा सभीराज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंकोएकमाडलबिलपरिचालितकियागया हैताकिवेभूजलकेविकासकेविनियमनकेलिएउपयुक्तभूजलकानूनका अधिनियमन करसकें, जिसमेंवर्षाजलसंचयनऔरभूजलपुनर्भरणकेप्रावधानभीशामिलहैं। अबतक 21 राज्यों/संघराज्यक्षेत्रोंद्वारा भूजलकानूनकोअपनायाऔरइसका कार्यान्वयन कियागया है।

(ड):केंद्रीयभूजलप्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वाराअधिकांशराज्योंमेंअपनेदिनांक 24.09.2020 केदिशानिर्देशों,जिनकीअखिलभारतीयप्रयोज्यताहै,केप्रावधानोंकेअनुसारदेशमेंभूजलके निष्कर्षणएवं

उपयोगको एनओसीजारीकरविनियमितकियाजाताहै। इन दिशा-निर्देशोंकेअनुसारवैधअनापत्तिप्रमाण-पत्रकेबिनाभूजलका निष्कर्षण करनेवालीपरियोजनाओंपरपर्यावरणीयक्षतिपूर्ति (ईसी) प्रभारलगाएजारहेहैं। इसकेअतिरिक्त, अनापत्तिप्रमाणपत्रकी शर्तोंकेउल्लंघन, भूजलकेअधिकनिष्कर्षण, निष्कर्षण किए गए भूजलकोमापनेकेलिएपीजोमीटरों/जलप्रवाहमीटरोंकीस्थापना न करनेआदिपर कठोरदंडकाभीप्रावधानकियागयाहै।

(च):भारतसरकारद्वारा

राज्योंकोभूजलकेसंरक्षणकेलिएजलकुशलसिंचाईतकनीकोंकोअपनानेकेलिएअपनेकिसानोंपरजोरदेनेकेलिएनिरंतर प्रोत्साहितकिया जा रहा है। इससंबंधमें, इस समयसूक्ष्मसिंचाईको अपनानेकेलिएप्रोत्साहनके उद्देश्य से निम्नलिखितयोजनाएंकार्यान्वितकीजारहीहैं:

- i. केंद्रसरकारद्वारा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थानऔरउत्तरप्रदेशराज्योंमेंजलकी कमी वाले 80 जिलोंमेंअटलभूजलयोजनाका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसस्कीमकामुख्य उद्देश्यग्रामीणस्तरोंपरस्थानीयसमुदायोंकोशामिलकरतेहुएक्षेत्रकेजलबजटपरआधारितवैज्ञानिकसाधनोंकेमाध्यमसेमांगपक्षप्रबंधनकरनाहैजिससेलक्षितक्षेत्रोंमेंस्थायीभूजलप्रबंधनसंभव होसके।
अटलजलयोजनाकेतहतड्रिपऔरस्प्रिंकलरकेउपयोगजैसीजलकुशलसिंचाईप्रथाओंकोबढ़ावादेना औरकिसानोंकोकमजल कीआवश्यकतावालीफसलोंको अपनाने केलिएप्रोत्साहितकरना इसकेप्रमुखलक्षित क्षेत्रहैं।
- ii. कृषिऔरकिसानकल्याणविभाग (डीएंडएफडब्ल्यू), भारतसरकार, द्वारा वर्ष 2015-16 सेदेशमेंप्रतिबूंदअधिकफसलयोजनाका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्मसिंचाईकेमाध्यमसेखेतस्तरपरजलउपयोगदक्षताबढ़ानेऔरउपलब्धजलसंसाधनोंकेइष्टतम उपयोग केलिएबेहतरऑन-फार्मजलप्रबंधनप्रथाओंपरकेंद्रितहै।

अनुलग्नक-1

'विभिन्न राज्यों में भूजल क्षरण की दर' के संबंध में दिनांक 13.03.को लोक सभा में 2025 उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2463 भाग) के उत्तर में उल्लिखित (अनुलग्नक।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जबलपुर प्रभाग के लिए तुलनात्मक भूजल संसाधन आकलन (वर्ष 2017 और 2024)

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र	वार्षिक भूजल पुनर्भरण (बीसीएम)		वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (बीसीएम)		सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण (बीसीएम)		निष्कर्षण का चरण (एसओई) (%)	
		2017	2024	2017	2024	2017	2024	2017	2024
1	पंजाब	23.93	19.19	21.58	17.63	35.78	27.66	165.77	156.87
2	हरियाणा	10.15	10.32	9.13	9.36	12.50	12.72	136.91	135.96
3	राजस्थान	13.21	12.58	11.99	11.37	16.77	17.05	139.88	149.86
4	जबलपुर प्रभाग	6.19	5.68	5.83	5.38	2.38	2.52	40.82	46.88

जबलपुर प्रभाग में मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी जिले शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

‘विभिन्न राज्यों में भूजल क्षरण की दर’ के संबंध में दिनांक 13.03.को लोक सभा में 2025 उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2463 भाग)ख के उत्तर में (उल्लिखित अनुलग्नक।

हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए औसत (मानसून श्चात वर्ष 2019 से 2023) और मानसून श्चात 2024 (अरिद्ध जलभृत) के साथ राज्यवार जलस्तर में उतार-चढ़ाव (मीटर में)

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र	विश्लेषण किए गए कुओं की संख्या	विभिन्न उतार-चढ़ाव मीटर की सीमा में कुओं की संख्या										कुओं की कुल संख्या				
			उतार					चढ़ाव					चढ़ाव	उतार			
			0 से 2 (मीटर)	2 से 4 (मीटर)	> 4 (मीटर)	%	%	0 से 2 (मीटर)	2 से 4 (मीटर)	> 4 (मीटर)	%	%				%	
1	हरियाणा	163	61	37.4	11	6.77	4.3	57	35	19	11.7	8	4.9	79	48.5	84	51.5
2	पंजाब	174	43	24.7	9	5.24	2.3	74	42.5	30	17.2	13	7.5	56	32.2	117	67.2
3	राजस्थान	824	263	31.9	120	14.6	132	163	19.8	61	7.4	85	10.3	515	62.5	309	37.5
4	जबलपुर प्रभाग	179	53	29.6	6	3.45	2.8	102	57	9	5	3	1.7	64	35.8	114	63.7

जबलपुर प्रभाग में मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी जिले शामिल हैं।
